

# बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

17 मार्च 2020

----

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ].

21

----

## नियुक्ति का प्रावधान

\*196 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि आज के आधुनिक जीवन शैली के कारण आमजनों को उनके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में एक्यूप्रेसर चिकित्सा पद्धति काफी सहायक सिद्ध हो सकती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस पद्धति / थेरेपी से रक्त संचार बढ़ाने अथवा नियमित करने के साथ-साथ मांसपेशियों की तकलीफों से भी निजात पाया जा सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी अनुमंडलीय तथा जिला अस्पतालों में जनहित में एक्यूप्रेसर थेरेपिस्ट का पद सृजित कर नियुक्ति का प्रावधान करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

----

## बंद इकाईयों को चालू

\*197 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बियाडा के अद्यौगिक क्षेत्रों में 2538 कुल इकाइयों में से 470 इकाई बंद हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बंद इकाइयों को चालू करने के लिए कौन-सा उपाय कर रही है?

----

### डॉक्टर की नियुक्ति

\*198 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में राज्य के दूर-दराज एवं सीमावर्ती राज्यों से हार्ट रोग से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में मरीजों की तुलना में हृदय रोग डाक्टरों की संख्या काफी कम है, जिससे हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए सप्ताहभर का इन्तजार करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में इलाज के लिए मात्र तीन ही मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनमें सिर्फ एक मशीन चालू अवस्था में है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने तथा नये उपकरण लगाने का विचार रखती है ताकि मरीजों की सुलभ चिकित्सा हो सके, यदि नहीं तो क्यों ?

----

### योजना का लाभ

\*199 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार ):

अल्पसंख्यक कल्याण :-

क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

क. क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार लोगों को एक से पाँच लाख तक का ऋण देने की योजना है?

ख. क्या यह सही है कि इस हेतु जिला स्तरीय चयन समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष डीडीसी एवं सचिव जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं?

ग. क्या यह सही है कि 2017-18 में 168 आवेदन को जिला चयन समिति ने स्वीकृत कर

विभाग को भेजा गया जिसमें मात्र 24 आवेदकों को ही इस ऋण का लाभ मिल पाया है?

घ. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बचे हुए स्वीकृत आवेदकों को इस योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### योजना शुरू

\*200 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार डेढ़ लाख किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त मोटर पंप तीन हॉर्स पावर (एच.पी.) का देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना का क्रियान्वयन पावर ग्रिड के माध्यम से होगा;

(ग) क्या यह सही है कि इस पंप से बिजली की बचत होगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक किसानों के हित में इस योजना को शुरू कराना चाहती है ?

----

### आरोपों की जांच

\*201 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय अवर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने पत्रांक-797, दिनांक-06.08.2019 और बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री ने क्रमशः पत्रांक-955, दिनांक-11.09.2019, पत्रांक-390/391/392, दिनांक-06.01.2020 के द्वारा सिविल सर्जन, भोजपुर (आरा), जिलाधिकारी, भोजपुर, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना तथा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को डा. आशुतोष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अगिआंव, भोजपुर के लेखापाल से तालमेल कर जननी बाल सुरक्षा योजना/ रोग कल्याण समिति के माध्यम से जाली विपत्र से लाखों रुपयों का गबन करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल के पत्रांक-797, दिनांक-06.08.2019 के आलोक में सिविल सर्जन, भोजपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अगिआंव के द्वारा आरोप से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जानेके कारण जांच नहीं की जा सकी;

(ग) उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अगिआंव को तत्काल वहां से स्थानांतरित कर तत्संबंधी उनके ऊपर लगाये गए आरोपों की जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

----

### बरारी प्रखंड अंतर्गत मोहनाचांदपुर में स्वास्थ्य केंद्र खोलने के सम्बन्ध में

**\*202 श्री अशोक कुमार अग्रवाल ( कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क. यह सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड अंतर्गत मोहनाचांदपुर (प्रतापगंज) में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मौजा-मोहनाचांदपुर, खाता सं०-188, खेसरा सं० – 1591, रकवा-1 बीघा जमीन अर्जित किया गया ?

ख. क्या यह सही है की अर्जित भूमि पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र का पक्का भवन निर्माण किया गया परन्तु किसी कारणवश न्हों अधुरा रह गया, जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है?

ग. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलाएगी की अर्ध निर्मित पक्का भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

----

### वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेन्स

**\*203 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

**उद्योग :-**

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत वर्ष 2019-20 में 1294 आवेदन ऑनलाइन एस.आई.पी.बी. को प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि एस.आई.पी.बी. द्वारा 1134 इकाइयों को स्टेज 1 क्लीयरेन्स दिया गया है जिसमें 16,144 करोड़ रुपये निवेश की राशि है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए 1294 इकाइयों के द्वारा आवेदन किया गया था लेकिन एस.आई.पी.बी. के द्वारा मात्र 275 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि उद्योग स्थापित करने के लिए 859 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से राज्य में नए उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति हतोत्साहित हो रहे हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि राज्य में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस लंबित क्यों है ?

----

### डाक्टर की प्रतिनियुक्ति

**\*204 श्री राजन कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के सदर अस्पताल में आई.सी.यू. रूम बनकर तैयार है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में आई.सी.यू. संचालन हेतु डाक्टर नहीं रहने के कारण आई.सी.यू. बंद पड़ा है;

(ग) क्या यह सही है कि आई.सी.यू. बंद पड़े रहने के कारण गरीब मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक दोहन से गुजरना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सदर अस्पताल में आई.सी.यू. के सूचारु रूप से संचालन हेतु डाक्टर प्रतिनियुक्ति कब करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

----

### बकाया का भुगतान

**\*205 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

**गन्ना उद्योग :-**

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में चीनी मिल, लौरिया में लौरिया के गन्ना किसानों का पेराई वर्ष-2017-18, 2018-19 एवं 2019-2020 का गन्ना

मूल्य करोड़ों रुपये बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि लौरिया चीनी मिल के द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने से लौरिया के गन्ना किसानों के परिवारों के बच्चों का पठन-पाठन बाधित है तथा भोजन की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

(ग) क्या उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लौरिया चीनी मिल से बकाये गन्ने का मूल्य का भुगतान किसानों को कबतक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

-----

### कार्रवाई पर विचार

\*206 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि आयुष्मान भारत योजना में राज्य के लिए आवंटित राशि के खर्च नहीं होने तथा खर्च की गई राशि का ब्योरा केन्द्र को नहीं भेजने की वजह से बिहार को मिलने वाली राशि को रोक दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि आयुष्मान भारत केन्द्र और राज्य सरकार की साझेदारी वाली योजना है तथा किसी कारणवश राज्य सरकार केन्द्र को आंकड़ा नहीं भेजती या राशि का 75 फीसदी हिस्सा खर्च नहीं कर पाती तो केन्द्र राशि रोक देती है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6400 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे जिसे अब घटाकर 3200 करोड़ कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि ऐसी लापरवाही विभाग के द्वारा क्यों की गई तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई योजना है; ?

-----

### स्वास्थ्य केन्द्र का पुनर्निर्माण

\*207 श्री सी.पी. सिन्हा उर्फ चन्द्रेश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अन्तर्गत एकमा विधानसभा के लहलादपुर में

स्वास्थ्य केन्द्र है जो जर्जर स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र आस-पास के लोगों का एकमात्र स्वास्थ्य केन्द्र है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

\*208 श्री सोने लाल मेहता (विधान सभा):

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनुपरा के ग्राम धनुपरा में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि धनुपरा ग्राम में राज्य सरकार की जमीन मुख्य सड़क के बगल में उपलब्ध है, जिसका खाता-930, खेसरा-2487, 41 डिसिमल है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन हेतु राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट, जिला पदाधिकारी, सहरसा को दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार धनुपरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

----

जिला जमुई चकाई प्रखंड के पंचायत कियाजोरी ग्राम पंजराडीह में आज तक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है और पोल तार लगाने के लिए संवेदक के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है।

\*209 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):

ऊर्जा :-

क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि चकाई प्रखंड अंतर्गत पंचायत कियाजोरी ग्राम पंजराडीह में बिजली विभाग के पदाधिकारी एवं संवेदक के द्वारा लापरवाही बरता जा रहा है आज तक इस गांव में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया और पोल तार लगाने के लिए संवेदक के द्वारा ग्रामीणों से

पैसा का मांग किया जा रहा है। (ख) क्या यह सही है कि इस तरह से चकाई विधानसभा अंतर्गत कई गांव में इस तरह का शिकायत मिल रहा है लेकिन उस पर विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कोई अमल नहीं किया जा रहा है। (ग) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गांव में ट्रांसफार्मर लगवाना चाहती है एवं दोषी संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों।

----

## हर घर नल का जल योजना में घटिया सामाग्री लगाकर सरकारी राशि की लूट

\*210 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार ):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क. क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा सात निश्चय योजना अर्न्तगत हर घर नल का जल योजना चल रही है;

ख. क्या यह सही है कि वैशाली जिले के महुआ, पातेपुर एवं जन्दाहा आदि प्रखंड में उक्त योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितता बरती गयी है तथा मानक से काफी घटिया स्तर के पाइप एवं अन्य सामाग्री का उपयोग कर सरकारी राशि का बंदरबॉट कर लिया गया है ;

ग. क्या यह सही है कि हर घर नल का जल योजना पूरी तरह से राज्य मे अभी तक पूर्ण भी नहीं हुई है कि इसमें लगाये गये पाईप जगह —जगह से टूट-फूट गये या लीक कर गये है जिसके कारण उक्त प्रखंडो मे

ग. हर घर नल का जल योजना पूरी तरह से विफल है ;

घ. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडो में आमजन को हर घर नल का जल योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने तक पेय जल का वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए घटिया सामाग्री लगाकर सरकारी राशि को लूटने वालो के विरुद्ध जाँच करकर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?

----

## मंदिर का अधिग्रहण

\*211 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):



**विधि :-**

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड स्थित मठ शिव मंदिर, बिहार राज्या आवास बोर्ड की जमीन पर है, जिसके एक हिस्से में 100 साल पुराना शिव मंदिर है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित शिव मंदिर का आज तक धार्मिक न्यास पर्वद द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिसके कारण उसका प्रबंधन समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित शिव मंदिर का अधिग्रहण धार्मिक न्यास पर्वद से कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### **चिकित्सकों की व्यवस्था**

**\*212 श्री टुनजी पाण्डेय (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि आयुष चिकित्सकों की नई सेवाशर्त नियमावली से नये बेरोजगार आयुष चिकित्सकों को सेवा में आने से सरकार क्यों रोक रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इस नियमावली में सरकार अनुभव के 25 अंकों का लाभ देकर क्यों पुराने चिकित्सकों को ही नये सृजित पदों पर रखना चाहती है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार पहली बार बेराजगार/नये आयुष चिकित्सकों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रही है, जिससे 2300 पदों में एक भी नये चिकित्सक को सेवा का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में एस.टी.ई.टी. के पात्रता में जिस तरह शिक्षकों की उम्र-सीमा में दस वर्षों की छूट दी गयी है, वैसा चिकित्सकों की नियुक्ति में दे रही है क्या ?

----

### **कार्रवाई पर विचार**

**\*213 श्री दिनेश प्रसाद सिंह (मुज्जफरपुर स्थानीय प्राधिकार ):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-217(ए) दिनांक-16.02.2017 द्वारा स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए मूल कोटि का पद राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना में चिन्हित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पदाधिकारी स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के प्रति रोष की भावना से ग्रसित होकर करीब तीन वर्षों की अवधि बीत जाने के बावजूद भी चिन्हित पदों पर पदस्थापना नहीं कर रहे हैं और नियम के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मूल कोटि के चिन्हित पदों पर कबतक पदस्थापना करते हुए इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार अधिकारी को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

----

### **ब्लड बैंक की स्थापना**

**\*214 श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि जयनगर अनुमंडल (मधुबनी जिला अन्तर्गत) में ब्लड बैंक की स्वीकृति वर्षों पूर्व मिल चुकी है, इसके बावजूद जयनगर ब्लड बैंक की स्थापना कर ब्लड संरक्षण का कार्य नहीं हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक जयनगर में ब्लड बैंक की स्थापना कर ब्लड संरक्षण का काम करना चाहती है ?

----

### **एम.आर.आई एवं सिटी स्कैन की सुविधा**

**\*215 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार ):**

**स्वास्थ्य :-**

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में एम.आर.आई. सहित सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से आम जनता को काफी कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन मशीनों

को लगाने की कोई योजनाएं बना रही हैं, यदि हां तो कबतक ?

-----

### विद्युत मीटर लगाने पर विचार

\*216 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार ):

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में बिजली मीटर लगाने हेतु आवेदन देने के बावजूद भी अस्सी प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीटर अभी तक नहीं लगाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मीटर नहीं लगने के कारण उपभोक्ता टोका लगाकर बिजली जलाते हैं जिसके कारण लो वोल्टेज या बराबर फॉल्ट लगता रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिले में जमा आवेदन के आलोक में उपभोक्ता को शीघ्र मीटर लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

-----